सेंटर फॉर इन्टरनेट एन्ड सोसाइटी | टैटल सिविक टेक

ऑनलाइन लिंग और यौन आधारित हिंसा को समझें, रिपोर्ट करें, संग्रहीत करें और समझें की उससे कैसे जूझे।

- भारत में ऑनलाइन लिंग और यौन यौन आधारित हिंसा को अपराध के रूप में क्यों नजरअंदाज किया जाता है?
- 02. कानून को समझें : लिंग और यौन अधारित हिंसा की 13 अभिव्यक्तियाँ ।
- 03. ऑनलाइन हिंसा को कैसे संगृहीत करें?
- 04. ऑनलाइन हिंसा को कैसे रिपोर्ट करें?
- 05. लिंग और यौन आधारित हिंसा से लड़ने के लिए अन्य सामुदायिक प्रयास।

यह दस्तावेज़ इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी सूचना को इखट्टा कर प्रस्तुत करता जो भारत में ऑनलाइन लिंग और यौन हिंसा को समझने और कम करने में पाठक की मदद करेगा।

इसे उली के साथ एक संसाधन के रूप में विकसित किया गया है। उली, एक ट्विटर प्लग-इन है जो भारत में यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन कंटेंट से लड़ने की क्षमता देता है। फिलहाल, उली तीन भाषाओं में उपलब्ध है: हिंदी, अंग्रेजी और तमिल।

आप इस टूल को यहां डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: uli.tattle.co.in



01.

भारत में ऑनलाइन लिंग और यौन यौन आधारित हिंसा को अपराध के रूप में क्यों नजरअंदाज किया जाता है?

पाँच आसान कारण

अपराध को उसकी क्रूरता के हिसाब से बांटा जाता है। ऑनलाइन लिंग और यौन आधारित हिंसा को क्रूर नहीं समझा जाता। लिंग और यौन आधारित हिंसा पर केंद्रित कानूनों का अभाव।

अधिकारियों के प्रशिक्षण/ट्रेनिंग का अभाव।

समाज की रूढ़िवादी सोच ।



लिंग और यौन आधारित हिंसा से जुड़े मामलों की कम रिपोर्टिंग।

सरकार और पुलिस अपना समय "असली" अपराध जैसे की बलात्कार और हत्या में अपना समय और ऊर्जा खर्च करना ज़रूरी समझते हैं।

इस बारे में और जाने : https://tinyurl.com/4x7vc447

लिंग और यौन आधारित कानून को समझें

"भारत में, ऑनलाइन लिंग और यौन आधारित हिंसा के मामले दो मुख्य कानूनों के अंतर्गत आते हैं: इंडियन पीनल कोड और द इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट"।

"पितृत्ववाद और नैतिक सेंसरशिप में डूबी [...], इंडियन पीनल कोड ऑनलाइन लिंग-आधारित हिंसा की नई अभिव्यक्तियों को समझने में सक्षम नहीं है"।

"ऐसे में केवल अश्लीलता विरोधी/ एन्टी ऑब्सेनिटी प्रावधानों पर भरोसा करना पड़ता है।"

"अश्लीलता विरोधी/ एन्टी ऑब्सेनिटी प्रावधान सरकार को किसी भी तरह की यौन अभिव्यक्ति को अपराध के रूप में देखने की अनुमति देते हैं और पुलिस को यौन और लैंगिक अल्पसंख्यों को कण्ट्रोल करने की इज़ाज़त अगर वह अभिव्यक्ति उनके हिसाब से अभद्र मानी जाए। "

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में धारा 66ई जैसे कुछ अन्य प्रगतिशील विकल्प हैं; हालांकि, इनका शायद ही उपयोग किया जाता है।"

इसके अलावा, "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक व्यवसाय-उन्मुख कानून है जो कि लिंग और यौन आधारित पहचान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और और लिंग-आधारित हिंसा पर मामूली दृष्टि डालता है"।

इस बारे में और जाने :

- https://tinyurl.com/2p963jnc
- https://www.apc.org/sites/default/files/ /Erotics_1_FIND.pdf

[अधिक जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध]

लिंग और यौन आधारित हिंसा की 13 अभिव्यक्तियाँ।

भारत में कानून की उपरोक्त सीमाओं के बावजूद, कुछ प्रावधान हैं जिनका उपयोग भारत में ऑनलाइन लिंग और यौन हिंसा के मामलों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

धारा <u>65:</u> कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग से संबंधित।

<u>धारा 67:</u> संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच से संबंधित।

बिना पूछे किसी की निजी इन्फॉर्मेशन निकालना , या डिवाइस यूज़ करना या उसके खाते को ब्लॉक करना

1

कौनसे कानून के तहत यह आता है? Sections 65, 70, and 72: डेटा चोरी से सम्बंधित।

सूचना का नियंत्रण और हेरफेर

सूचना एकत्र करना और चोरी यानी ऐसी जानकारी पर निजी नियंत्रण खोना और निजी जानकारी का अनधिकृत हेरफेर। it

प्रतिरूपण और पहचान की चोरी

किसी की सहमति के बिना किसी की पहचान का उपयोग करना या जालसाजी कौनसे कानून के तहत यह आता है?

Section 66C of the IT Act पहचान की चोरी से सम्बंधित।

3

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

धारा 354D (आई पी सी) साइबर निगरानी से सम्बंधित। धारा 72 में गोपनीयता या गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है'।

निगरानी और पीछा

किसी व्यक्ति की गतिविधियों, दैनिक जीवन या सूचना की निरंतर निगरानी [चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी]

भेदभावपूर्ण भाषण / स्पीच

भाषण /स्पीच जो रूढ़िवादी सोच के माध्यम से भेदभाव को बढ़ावा देता हो। ऐसा भाषण हिंसा को भड़का सकता है या नहीं।

कौनसे कानून के तहत यह आता है? लिंग या यौन-आधारित अभद्र भाषा के खिलाफ कोई कानून नहीं। The Indecent Representation of Women (Prohibition) Amendment Bill, 2012 को ऑडियो विजुअल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को कवर करने के लिए विस्तृत किया गया है।

लिंग और यौन आधारित हिंसा की 13 अभिव्यक्तियाँ।

भारत में कानून की उपरोक्त सीमाओं के बावजूद, कुछ प्रावधान हैं जिनका उपयोग भारत में ऑनलाइन लिंग और यौन हिंसा के मामलों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।

उत्पीड़न

किसी को बार-बार परेशान करना या धमकी देना। यह यौन आधारित भी हो सकती हैं और नहीं भी।

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

आई टी एक्ट की धारा <u>354A:</u> यौन अनुग्रह की मांग करना; ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफी दिखाना; धारा 503: धमकी देना डराना। धारा 509: महिलाओं की मॉडेस्टी उल्लंघन करना (इंटरनेट पर साझा की गई सामग्री भी इसमें शामिल है)

6

कौनसे कानून के तहत यह आता है? (आई पी सी)<u>धारा 503, 506, और</u>

<u>507: धमकी। मारना या मौत की</u> <u>धमकी।</u>

धमकी

भाषण और सामग्री (मौखिक या लिखित, छवियों आदि में) एक हिंसक, यौन आक्रामक या धमकी भरे स्वर के साथ जो किसी व्यक्ति, उनके परिवार या दोस्तों, या उनके सामान को नुकसान पहुंचाने का इरादा व्यक्त करता है

निजी जानकारी का गैर-सहमति साझाकरण

किसी व्यक्ति से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी, डेटा या निजी विवरण का अनिधकृत साझाकरण या प्रकाशन।

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

आईटी अधिनयम की धारा 66ई: निजी क्षेत्रों की छिवयों को किसी की सहमित के बिना कैप्चर करना, प्रकाशित करना या उनका प्रसार करना। अनुच्छेद 21: निजता का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है।

8

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

धारा 503: यह भी आपराधिक धमकी के तहत आता है।

जबरन वसूली

किसी व्यक्ति को किसी मूल्यवान चीज़ (जैसे व्यक्तिगत जानकारी, अंतरंग चित्र, आदि) के संबंध में धमकी और धमकी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करना।

तिरस्कार

मानहानि, धब्बा लगाना, और/या किसी व्यक्ति, समूह की विश्वसनीयता, करियर, काम या सार्वजनिक छवि को झूठी, हेरफेर या विषय से परे जानकारी के प्रसार के माध्यम से तिरस्कार करना।

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

Section 499:

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित कोई भी सामग्री से सम्बंधित

लिंग और यौन आधारित हिंसा की 13 अभिव्यक्तियाँ।

भारत में कानून की उपरोक्त सीमाओं के बावजूद, कुछ प्रावधान हैं जिनका उपयोग भारत में ऑनलाइन लिंग और यौन हिंसा के मामलों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी से संबंधित यौन हिंसा और शोषण

किसी की तस्वीरों और/या शरीर का शोषण करना जहां प्रौद्योगिकी एक मौलिक साधन है।

कौनसे कानून के तहत यह आता है?

धारा 67A (आई टी एक्ट) : प्रकाशन, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रसारण। धारा 67B: बच्चों को चित्रित करने वाली स्पष्ट सामग्री से संभंधित।

11

कोई कानूनी प्रावधान नहीं

संचार चैनलों पर हमले

किसी व्यक्ति या समूह के संचार या सूचना
चैनलों को जानभूझ कर ब्लॉक करना।

नियामक अभिनेताओं द्वारा चूक

अभिकर्ताओं (अधिकारियों, इंटरनेट मध्यस्थों, संस्थानों, समुदायों) द्वारा अवमानना या रुचि की कमी जिनके पास हमलों को विनियमित करने, हल करने और / या दंडित करने की विकल्प हैं।

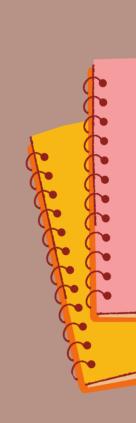
कोई कानूनी प्रावधान नहीं

लुचाडोरस, सोशलटिक और एपीसी द्वारा बनाए गए "13 Manifestations of oGBV" क अनुकूलन ।



ऑनलाइन हिंसा को कैसे संगृहीत करें? और यह क्यों ज़रूरी है?

"एक किठनाई जो अक्सर ऑनलाइन लिंग और यौन आधारित हिंसा के मुक़दम्मों में सामने आती है, वह है डिजिटल सबूत/ एविडेंस का उत्पादन। अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित अक्सर अपने उपकरणों को पुलिस कर्मचारियों को सौंपने से डरते हैं। सबूत हासिल करने में एक और बाधा यह है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म हमेशा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, यह दावा करते हुए कि वे अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। यदि डिजिटल सबूत सावधानीपूर्वक एकत्र नहीं किए जाते हैं, तो इसे अदालत में पेश करने की अनुमित नहीं दी जाती है।"



सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार "न्यायालय में डिजिटल सबूत के उत्पादन से जुड़े कुछ नियमों को कुछ मामलों में न्याय के हित में अदालत द्वारा ढीला किया जा सकता है"



ऑनलाइन हिंसा को रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है, भले ही आप इसकी रिपोर्ट न करें।



यूके स्थित संगठन, ग्लिच, के हिसाब से "हिंसा के स्क्रीनशॉट लेना और उन्हें एक फ़ोल्डर में दर्ज करना, घटना को दिनांक, समय और जगह के साथ एक साधारण तालिका में लॉग करना बहुत महत्वपूर्ण है । इस दस्तावेज में यह लिखना ज़रूरी है की घटना के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ था है, और कैसे चिंता, धमकी, या अधिक नुकसान का डर पैदा किया गया"।

आप ऑनलाइन हिंसा का दस्तावेजीकरण करने के लिए निम्नलिखित फॉर्म और ग्लिच द्वारा बनाए गए संसाधन का उपयोग कर सकते हैं::

<u>Documenting_Abuse_form_pdf</u>

[अधिक जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध]

अपनी पोस्ट संग्रहित करें:

आप उली के आर्काइव फीचर का उपयोग किसी भी आपत्तिजनक ट्वीट का स्क्रीनशॉट और रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। भविष्य में, हम यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन हिंसा का एक ऑनलाइन भंडार बनाने की भी उम्मीद करते हैं। यह भंडार शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन दुरुपयोग से लड़ने में मदद करेगा।







04

ऑनलाइन हिंसा को कैसे रिपोर्ट करें?

ध्यान रखने योग्य कुछ बहुत ही बुनियादी बात

01

साइबर अपराध के मामले में पीड़ित अपने नजदीकी साइबर सेल या पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकतें है।

02

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर अपराध.gov.in) के माध्यम से गुमनाम रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

03

हैकिंग के मामले में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:

- सर्वर लॉग।
- हैक की गयी वेबसाइट की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ उसकी हार्ड कॉपी।
- यदि आपके सर्वर या कंप्यूटर या किसी अन्य नेटवर्क उपकरण पर डेटा से छेड़छाड़ की जाती है, तो मूल डेटा और छेड़छाड़ किए गए डेटा की सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता होती है।
- एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म विवरण यानी छेड़छाड़ किए गए सिस्टम का किसके पास किस तरह कंट्रोल था।
- संदिग्धों की सूची यदि कोई हो।

04

ऐसी कोई भी जानकारी जो इन प्रश्नो के उत्तर दे :

- सिस्टम के साथ कैसी छेड़छाड़ करी गई है?
- सिस्टम से छेड़छाड़ किसने करी होगी?
- सिस्टम से छेड़छाड़ कब करी गई?
- सिस्टम से छेड़छाड़ क्यों करी गई होगी?
- कितने सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करि गई है?
- ई-मेल के दुरुपयोग जैसे अश्लील ई-मेल आदि के मामले में, निम्नलिखित जानकारी

05

अश्लील ई-मेल, पोस्ट आदि जैसे ऑनलाइन दुरुपयोग के मामले में, निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:

- आपत्तिजनक ई-मेल, या पोस्ट के यूआरएल के विस्तारित हेडर निकालें और सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ आपत्तिजनक ई-मेल/ पोस्ट संदेश की हार्ड कॉपी भी लाएं।
- कृपया आपत्तिजनक ई-मेल/पोस्ट/संदेश को अपने ई-मेल बॉक्स से न हटाएं।
- कृपया आपत्तिजनक पोस्ट/ई-मेल/संदेशों की कॉपी अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सेव करें।



05

सरकारी हेल्पलाइन और अन्य सामुदायिक प्रयास



एक बार पोर्टल पर शिकायत करने के बाद, शिकायतकर्ता से पूछताछ की जाती है कि क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज की है या सोशल मीडिया कंपनी (एसएमसी) के समक्ष शिकायत दर्ज की है। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो शिकायतकर्ता को सलाह दी जाती है एसएमसी के साथ शिकायत दर्ज करने और मंत्रालय के साथ संदर्भ संख्या साझा करने की। मिनिस्ट्री 7 से 10 दिनों के भीतर पुलिस या एसएमसी से पूछताछ करती है कि क्या कोई कार्रवाई की गई है। किसी भी कार्रवाई के अभाव में, मंत्रालय कदम उठाता

"यहां एसएमसी के साथ पुलिस की ताकत की तुलना करना भ्रमित करने जैसा प्रतीत होता है। यह सुझाव देकर कि एसएमसी को शिकायत की जाए, मंत्रालय पुलिस के पास जाने के बजाय एसएमसी मार्ग को मूल्य देता है।

Know more at:



"एसएमसी मार्ग को मूल्य देने से पता चलता है कि निवारण केवल सामग्री को हटाने और दुर्व्यवहार करने वाले की प्रोफ़ाइल को अवरुद्ध या बंद करने तक सीमित हो सकता है। यह प्रतिक्रिया व्यर्थ है क्योंकि वैकल्पिक/ नकली प्रोफाइल आसानी से बनाये जा सकते हैं । अगर सरकार यौन और लिंग-आधारित हिंसा से निपटने का इरादा रखती है तो उसे कानून प्रवर्तन में सुधार करना चाहिए। लिंग आधारित साइबर हिंसा के मामलों में गंभीर नुकसान को पहचानने, स्वीकार करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के लिए पुलिस और कानून के रूढ़िवादी विचारों को बदलने की जरूरत है।" (ibid.)



हिंदी और अंग्रेजी के लिए

@Team Saath: यह एक ट्विटर हैंडल है जो ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद करतें हैं।

Centre for Cyber Victims Counsellling

Social Media Matters Cyber helpline

> TechSakhi: हिंदी में डिजिटल सूचना हेल्पलाइन

तमिल के लिए।



Dhwani 24*7 toll free helpline by **PCVC** 044-43111143/ Whatsapp chat support: 9840888882

Under construction -கட்டப்பட்டு வருகிறது

आभार:

उली को ओमिडयार इंडिया नेटवर्क का समर्थन था । आप उलि का उपयोग अपने ट्विटर फ़ीड से समस्याग्रस्त पोस्ट को संग्रहित करने, संशोधित करने और छिपाने के लिए कर सकते हैं। उली के बारे में यहाँ और जानें: http://uli.tattle.co.in/ यदि आप यूली का उपयोग करते हैं और आपको सहायता की आवश्यकता है, तो हमें यहां लिखें: uli_support@tattle.co.in जानकारी चेष्टा अरोड़ा द्वारा एकत्रित और प्रस्तुत की गई है।

सेंटर फॉर इन्टरनेट एंड सोसाइटी | टैटल सिविक टेक